कुछ नहीं होता है। वहां पर लोग बड़े पैमाने पर जाते हैं, वह slippery होता है। गणपति उत्सव पर बड़े पैमाने पर कोंकणी लोग वहां पर जाते हैं, उन लोगों को हर समय बड़ी तकलीफ का सामना करना होता है। उनको वहां पर 24-24 घण्टे प्रवास करना पड़ता है, एक, दो किलोमीटर चलने के लिए 2-2 घण्टे लग जाते हैं। इस विषय पर आपको देखना चाहिए और नई technique का इस्तेमाल करना चाहिए। वे कुछ बनाते समय सिर्फ खड़ी और मिट्टी डालते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, बल्कि उससे टायर burst हो जाते हैं। इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। आज technique बहुत बढ़ गई है। अगर इसे जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे, तो हम लोगों के लिए ठीक होगा, कोंकणी लोगों को गणपति उत्सव ठीक होगा। सभापति महोदय, आप इनको आदेश दीजिए। इन्हें अपने स्टेट मिनिस्टर को बोलना चाहिए, लेकिन अभी तक four lane का काम भी ठीक से चलता हुआ दिखाई नहीं देता है।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Concern over flood and drought situation in Uttar Pradesh and other States

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): चेयरमैन सर, मैंने आपसे बाढ़ और सूखे पर अति महत्वपूर्ण लोकमत का प्रश्न उठाने की अनुज्ञा मांगी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान ने मई-जून में पूरे देश में घोषणा की थी कि अब की बार मानसून में ज्यादा से ज्यादा पानी बरसने की उम्मीद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कुछ राज्यों में बाढ़ आई है, वहीं कुछ राज्यों में सूखा भी पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब हर साल बाढ़ आती है, तो सरकार यह व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि बाढ़ से जो नुकसान होता है, उसको रोका जाए। ऐसा होना हर साल का धन्धा है। बाढ़ आने के बाद देश का हजारों करोड़ रुपया ज़ाया हो जाता है और बाढ़ के जाने के बाद तमाम तरह की बीमारियां पूरे देश में फैल जाती हैं। जहां-जहां बाढ़ आती है, वहां ऐसा ही होता है। उसकी रोकथाम होनी चाहिए।

महोदय, मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अन्य राज्य, जहां-जहां सूखा पड़ा है, वहां एक टीम भेजनी चाहिए और उस टीम के द्वारा आकलन किया जाना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है।

महोदय, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए एक बीमा योजना बनाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका भुगतान नहीं होता है और उसका गलत उपयोग भी होता है। मैं चाहूंगा कि इस पर आपका निर्देश आना चाहिए।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Molestation of 40 girls in a girl's hostel run by an NGO in Muzaffarpur

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): सभापति महोदय, मैं एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, जिससे आप स्वयं और इस पूरे सदन में तमाम पक्ष के लोग आंदोलित होंगे, उसका ज़िक्र करना चाहता

हूं। मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना के बारे में कहना चाहता हूं। सर, एक निर्भया ने इस पूरे देश को आंदोलित किया था, यहां 40 से ज्यादा निर्भयाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। Contract किसी और के नाम से था, जबकि संचालन कोई और कर रहा था। नतीजतन आज यह हुआ है कि हमारे इस मुल्क में, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल में हों, लेकिन हमारी बेटियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए बालिका गृह भी महफूज़ जगह नहीं है। सड़कों के बारे में समझा जा सकता है कि वहां और कोशिशें करनी होंगी, लेकिन बालिका गृह के अन्दर ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार): सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है।

श्री सभापतिः आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

प्रो. मनोज कुमार झाः सर, मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि इस तरह के मसलों पर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूं। Tata Institute of Social Sciences की Social Audit Report है। बहुत दिनों से यह रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के माध्यम से यह ज़ाहिर हुआ कि यह systematic pattern था। सर, अगर एक प्रणाली के तहत हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो हम कौन सा मुल्क बना रहे हैं? आवश्यकता इस बात की है कि इस पर सदन का एक पूरा का पूरा दृष्टिकोण जाना चाहिए। सर, इस NGO का बड़ा अच्छा नाम है - "सेवा संकल्प"। सर, न सेवा है, न संकल्प। आज परिस्थितियां ये हो गईं हैं कि बच्चियां महफूज़ नहीं हैं। बच्चियों के कहने पर उस जगह की खुदाई हो रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कुछ बच्चियों की हत्या भी हुई है। सर, मैं हाथ जोड़ कर आपसे विनती करती हूं, क्योंकि एक-एक घटना जिस प्रकार की हुई है, वह यह बता रही है कि हम कौन से गणतंत्र में जी रहे हैं। अगर बच्चियां महफूज़ नहीं हैं, वे सड़कों पर नहीं चल सकतीं, स्कूल-कॉलेज में महफूज़ नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा मंगल यान बेमानी है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापतिः यह विषय गम्भीर है। I hope the concerned agencies will take note of the same. If Members cooperate, I can still go ahead with some more names.

श्रीमती अम्बिका सोनी (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूं।

कुमारी शैलजा (हरियाणा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करती हूं।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री शमशेर सिंह ढुलो (पंजाब): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO (Telangana): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI VIVEK K. TANKHA (Madhya Pradesh): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI SANTIUSE KUJUR (Assam): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

SHRIMATI M.C. MARY KOM (Nominated): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

कुछ माननीय सदस्य: महोदय, हम भी स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

Plight of students who have taken education loans from Public Sector Banks

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, since higher education is getting costlier in the country, students not only from economically weaker sections but also the students who are the first-generation graduates and even those who belong to middle class families rely upon education loans from the public sector banks. Of course, the education which they get does not translate into employment. Soon after their education is over, they don't get employment. Even those students, who are very qualified, are not able to get employment. So loan repayment is not easier for many of these students. But the problem is that between the date of getting education loan and the date of repayment, there is interim period, and for that also, the bank is collecting interest. I have with me the details of a case. A student got, in six instalments, Rs.1,76,990 as loan. He repaid Rs.2,82,047 which includes the principal amount of Rs.1,76,990 and Rs.1,05,000 as interest. But apart from that, the bank is asking him to repay interest which is to be collected from the period when it was commenced.

Sir, our demand is very, very simple. The Government should take the responsibility. Before repayment schedule starts, the interest should be borne by the Government or the banks should waive it.